Discontinuance of relief work in drought affected areas of Madhya Pradesh

1323. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradseh Government has decided to discontinue the relief works in Indore and various other Division in the State;

(b) whether it is also a fact that there are still large number of drought affected people who have not got relief so far; and

(c) if so, what are the reasons for discontinuance of the relief work and to what extent it would affect the people?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) Yes Sir. The State Government has issued instructions to discontinue relief works in Indore and Ujjain divisions with effect from 31st July, 1988. In other divisions of the State the relief work have already been stopped since 15th July, 1988.

(b) and (c) State Government have reported there are no drought affected people who have not got relief. The majority of people in the rural areas got busy with the sowing and other agricultural operations. The remaining persons are getting employment on normal plan works and NREP/RLEGP works. Taking into account satisfactory rainfall position and commencement of agricultural operations, the State Government decided to discontinue the relief works gradually.

Rise in prices of foodgrains etc.

1324. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state whether it is a fact that prices of foodgrains, pulses, edible oils and stapple vegetables have been registering unprecedented rise all over the country since July, 1987 despite adequate stock of foodgrains good kharif yield last season and higher oil seeds and sugarcane production during 1987-88?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): Between the terminal week of June 1987 and July 16, 1988 there has been a mixed trend in the prices of essential commodites. The prices of some commodities have moved up, some have moved down and the few have remained more or less steady.

मध्य प्रदेश के बस्तर आदिवासी क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति

1325. **श्री अजीत जोगी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिले बस्तर में लगभग 1000 स्थानों पर नलकूपों के पानी में लौह अयस्क के कण होने से वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं की जा सकी है ;

(ख) यदि हां, तो इन आदिवासियों को स्वच्छ पेय जल कैसे उपलब्ध कराया जायेगा; और

(ग) उस जिले में फिल्टर आदि लगाने पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कब तक धन उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को बस्तर जिले में भू-जल में लौह समस्या की जानकारी है ।

(ख) गांवों में अतिरिक्त ट्यूबवैलों के जरिए और जिले में लौह दूर करने के संयंत्र स्थापित करने हेतु कार्यक्रम चलाकर भी पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अधिकांश गांवों में पीने के पानी के लिए एक ट्यूबवैल और हैण्डपम्प उपलब्ध किया जाता है और उनमें से कुछ लौह-मुक्त हैं। अब तक, ऐसे 80 संयंत्र उपलब्ध किये जा चुके हैं ;

(ग) लौह दूर करने के संयंत्र लगाने के लिए योजनाओं के अनुमोदन के बाद ही राज्य सरकार को निधियां प्रदान की जायेगी, जिसके लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

आदिवासी तथा पहाड़ी इलाकों में परम्परागत फसलों के लिए अनुसंधान कार्य

1326. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी तथा पहाड़ी इलाकों में पैदा की जाने वाली परम्परागत फसलों की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए कोई अनुसंधान सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र कहां-कहां स्थापित हैं; और

(ग) इन अनुसंधानों के लाभों को आदिवासी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में उगाई जाने वाली परम्परागत फसलों की उपज बढ़ाने में लगी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के सभी अनुसंधान संस्थानों और केन्द्रों की सूची अनुपत्र में दी गई है । [देखिये परिशिष्ट CXLVII अनुपत्र सं० 54]

(ग) आदिवासियों की आमदनी को बढाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.), राष्ट्रीय प्रदर्शनों, किसान के खेतों में प्रदर्शन, किसान मेला, कार्यशाला का आयोजन तथा नई किस्मों के बीज मिनिकिटों और सुधरी उत्पादन प्रौद्योगिकि की सप्लाई करते रहे हैं । इसके अलावा आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान और उनकी स्थिति सुधारने के लिए दो व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाएं भी चलाई जा रही हैं । इनमें से एक आदिवासी इलाकों के लिए है और दूसरी अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातियों के लिए है ।

Relay of Regional News bulletins through Jaipur

1327. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to relay regional news bulletins through Jaipur Doordarshan Kendra; and

(b) if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) Yes, Sir. Efforts are already under way to provide necessary man-power and other facilities to commence the telecast of regional news bulletin from Doordarshan Kendra, Jaipur.

Telecast of Mahabharat serial

1328. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the day when the serial Mahabharat is likely to be telecast from Doordarsan; and

(b) how many episodes of this serial are approved for telecast?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATON AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) The serial 'Mahabharat' has been approved for 52 episodes. The date of its telecast has not been decided.

1329. [*Transferred to the 9th August, 1988*]